ग्रा० वि०-4-9-वि-BRDS 21/2012

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 152135 / पटना, दिनांक 15.06.2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में ,

प्रधान सचिव,
सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग,
बिहार ।

विषय :- ई-शक्ति परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग कर मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ई-शक्ति परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । ई-शक्ति परियोजना राज्य में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्तमान में पटना जिला के 23 प्रखंडो में से 8 प्रखंडो यथा - बिहटा, नौबतपुर, संपतचक, बाढ़, विक्रम, दानापुर, दुल्हिन बाजार, फतुहा में मनरेगा की सभी योजनाओं का ई-शक्ति प्लेटफार्म पर क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं मजदूरों को BC के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ।

2. ई-शक्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक, उप विकास आयुक्त, पटना तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । समीक्षा के दौरान यह विदित हो रहा है कि विभाग के प्रयासों के बाबजूद ई-शक्ति परियोजना का कार्यान्वयन सही ढ़ग से नहीं हो पा रहा है । परियोजना के क्रियान्वयन में समय-सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है एवं विभागीय निदेशों का ससमय समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इससे ई-शक्ति परियोजना का विस्तार अन्य 37 जिलों में करने में जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो रही है ।

3. ई-शक्ति परियोजना को शीघ्र विस्तारित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है । इस परियोजना की मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 11.03.13 को हुई समीक्षा की कार्रवाई एवं विकास आयुक्त के स्तर पर हुई समीक्षा की कार्रवाई दिनांक 10.01.13 संलग्न कर भवदीय संदर्भ हेतु भेजी जा रही है ।

4. उपरोक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि भवदीय अपने स्तर पर यथोचित समीक्षा करके बेल्ट्रॉन को सरकार की महत्वाकांक्षी ई-शक्ति परियोजना के ससमय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशित करने की कृपा करना चाहेंगे ।

5. इस विषय पर भवदीय स्तर पर एक बैठक आयोजित करना श्रेयस्कर होगा जिसमें मैं एवं आयुक्त, मनरेगा भी भाग लेंगे ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

15.6.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

KL
13/6/13

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ई-शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही :-

ग्रामीण विकास विभाग के अनुरोध पर ई-शक्ति परियोजना की समीक्षा के लिए बैठक रखी गयी जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अलावे बेल्ट्रॉन के प्रतिनिधियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे । सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने ई-शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन पर ध्यान आकृष्ट किया कि ई-शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन की गति धीमी है । 3 बिन्दुओं पर बेल्ट्रॉन को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निम्नवत् है :-

(1) ई-शक्ति प्लैटफॉर्म का नरेगा साफ्ट के साथ इन्टीग्रेशन

(2) ई-शक्ति के अन्तर्गत मजदूरों की उपस्थिति कार्यस्थल पर लेने और geo tagging करने ।

(3) ई-शक्ति परियोजना के विस्तार के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा सेवा प्रदाता के साथ किये गये एग्रीमेन्ट के प्रावधानों के अनुरूप तृतीय पक्ष द्वारा पायलट के सफलता का स्वतंत्र partial acceptance test एवं final acceptance test की व्यवस्था ।

2- प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन द्वारा अपनी प्रस्तुति के दौरान इन सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी । उन्होंने परियोजना के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की और बताया कि पटना जिला के 5 प्रखंडों में यह परियोजना चल रही है जिसके अन्तर्गत मजदूरों की उपस्थिति और कार्य के मजदूरी का भुगतान ई-शक्ति प्लैटफार्म पर हो रहा है । अबतक लगभग 52 हजार मजदूरों को इस परियोजना के अन्तर्गत भुगतान हुआ है । बीच में यू0आई0डी0 के साथ इन्टीग्रेशन को लेकर कार्यान्वयन प्रभावित हुआ लेकिन अब सरकार ने यह स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि इसे राज्य में पूर्ण रूप से लागू करना है तब से कार्य में तेजी आयी है । उन्होंने सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आश्वासन दिया कि इन सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । उन्होंने बताया कि नरेगा साफ्ट के साथ इन्टीग्रेशन के लिए प्रयास किया गया है और इसे अगले 15 दिनों के अन्दर कार्य रूप दे दिया जाएगा ।

3- कार्य स्थल पर मजदूरों की उपस्थिति एवं geo tagging के लिए एजेन्सी द्वारा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसे शीघ्र ही कार्यरूप दे दिया जाएगा ।

4- partial acceptance test एवं final acceptance test पर उन्होंने बताया कि इस पर सक्षम स्तर पर विचार विमर्श होने के बाद अन्ततः जब कोई तृतीय पक्ष उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका BeST से independent evaluation करवाया गया है ।

5- विचार विमर्श के क्रम में यह प्रस्तुत किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कैबिनेट के अनुमोदन के क्रम में 20 करोड़ की राशि बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराने का निर्णय था । बेल्ट्रॉन ने ग्रामीण विकास विभाग से राशि की मांग की है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का आग्रह किया और बताया कि बेल्ट्रॉन के अनुरोध पर उन्हें 10 करोड़ रूपये की राशि तत्काल दी जा रही है जिसका बेल्ट्रॉन समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करेगा ।

6- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर साप्ताहिक तौर पर कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है लेकिन जिस तीव्र गति से इसका कार्यान्वयन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । इसलिए बेल्ट्रॉन एवं सेवा प्रदाता को तत्परता बरतने की आवश्यकता है ।

7- विकास आयुक्त ने यह निदेश दिया है कि यह परियोजना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है । इसके लिए बेल्ट्रॉन अलग से सेल गठित करे और तीव्र गति से गुणवत्तायुक्त, संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए परियोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे । पायलेट के आगे इसे विस्तारित किया जाना एवं तृतीय पक्ष evaluation भी अन्य संस्था से कराने की कार्रवाई की जाय ।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग, पटना

विकास आयुक्त,
बिहार

ज्ञापांक- 13798 पटना, दिनांक - 7/2/13

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ई.शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ई.शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गयी ।

2. आयुक्त मनरेगा द्वारा इस योजना के विस्तार की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गयी । प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और आगे विस्तार से संबंधित चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया ।

3. मुख्य सचिव द्वारा योजना के गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन एवं तीव्र प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए निर्देश दिया कि मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए । मनरेगा में यह शिकायत है कि कार्यान्वयन एजेंसी भौतिक रूप से कार्य नहीं करके अधिक कार्य दिखाकर राशि व्यय करती है, इस पर रोक लगायी जानी चाहिए ।

4. समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि पटना के 5 पॉयलट प्रखंडों में यह कार्य चल रहा है। पटना जिले के शेष 18 प्रखंडों में अगले महीने के शुरू से ई.शक्ति प्लेटफार्म पर मनरेगा का कार्यान्वयन होगा । अगले 3 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में बायोमैट्रिक्स डाटा संग्रहण कर लिया गया है वहाँ यद्यपि डाटा 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का किया गया है किन्तु प्रथम चरण में प्राथमिकता पर सक्रिय मनरेगा जॉब कार्डधारी व्यक्तियों के ई.शक्ति कार्ड बनाया जाएगा और अगले 3 महीने के अंदर परियोजना को उन जिलों में भी रोल आउट किया जाएगा ।

5. राज्य के अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से मार्च 2014 तक इस योजना को रोल आउट करने का प्रयास किया जाएगा ।

6. समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि कार्य के तेजी से विस्तार से यह आवश्यक है कि एक से अधिक कार्यान्वयन एजेंसी कार्य करें । इस हेतु बेल्ट्रॉन को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिया गया ।

7. समीक्षा के क्रम में मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गयी एवं निम्नवत निर्देश दिए गए :-

(i) मनरेगा में वर्तमान में मजदूरी 144 रूपये प्रतिदिन की दर से भुगतान की जा रही है । भारत सरकार ने अभी हाल में 138 रूपये प्रतिदिन की दर से मनरेगा की मजदूरी

अधिसूचित की है । इसकी समीक्षा करके 1 अप्रैल 2013 से राज्य में जो मजदूरी भुगतान करनी है, उसके संबंध में सक्षम आदेश प्राप्त किए जाएं ।

(ii) मनरेगा के बेहतर प्रबंधन के लिए समुचित मानव संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है । इस दृष्टिकोण से यह महसूस किया गया कि वर्तमान में 6% की मान्यता की सीमा के कारण मानव संसाधन में बढ़ोतरी करने में दिक्कत हो रही है । अतः राज्य योजना से सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करके उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

(iii) मनरेगा के कार्यान्वयन में परिसम्पत्ति सृजन पर जोर दिया जाय ।

(iv) इंदिरा आवास योजना की पूर्णता की स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया । साथ ही लक्ष्यानुसार उपलब्धि हासिल करने के लिए निर्देश दिया गया ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

(ए.के. सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 14350 दिनांक :- 26.3.13

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक :- _____ दिनांक :- _____

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक :- _____ दिनांक :- _____

प्रतिलिपि - आयुक्त मनरेगा / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना / श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी / श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव